Par. S.2.I.1.52
836

Volume I
No. 1 — 21

Friday
16 May, 1952

PARLIAMENTARY DEBATES

HOUSE OF THE PEOPLE

OFFICIAL REPORT

(Part II—Proceedings other than Questions and Answers)

CONTENTS

Members Sworn [Cols. 2—18].

PARLIAMENT SECRETARIAT
NEW DELHI

Price Six Annas (Inland)
Price Two Shillings (Foreign)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 25003
Dated 20/11/2014

THE PARLIAMENTARY DEBATES

(Part II—Proceedings other than Questions and Answers)

OFFICIAL REPORT

HOUSE OF THE PEOPLE

Friday, 16th May, 1952

The House met at Twelve Noon

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

QUESTIONS AND ANSWERS

(No Questions: Part I not published.)

MEMBERS SWORN

Shri Bhawanji A. Khimji [Kutch West]

Jonab Amjad Ali [Goalpara-Garo Hills]

Shri Chandrashanker Bhatt [Broach]

Shri B. Das (Jajpur-Keonjhar): I suggest that the Secretary should call out the names of Members who take the oath. I am afraid we cannot hear their names distinctly.

Mr. Speaker: Hon. Members while taking the oath read out their names themselves.

Shri B. Das: They do not speak loudly.

Mr. Speaker: The complaint is that they do not speak loudly. Very well, next time we shall do that.

PAPERS LAID ON THE TABLE.

PRESIDENT'S ADDRESS

Secretary: I beg to lay on the Table a copy of the President's Address to both Houses of Parliament assembled together this morning.

राष्ट्रपति: संसद् के सदस्यो, भारतीय गणतन्त्र की इस पहली संसद् के, जो हमारे

संविधान के अनुसार चुनी गई है, सदस्यों की हैसियत में आप लोगों का मैं यहां स्वागत करता हूं। विधान सभाओं की रचना और राज्य के अधिपति सम्बन्धी संविधान के उपबन्धों का हमने पूरी तरह से अमल दरामद कर दिया है और इस तरह अपने सफर की एक मंजिल पूरी कर ली है। जैसे ही यह मंजिल समाप्त होती है दूसरी मंजिल शुरू हो जाती है। किसी भी जाति या राष्ट्र के लिये अपने आगे की यात्रा में आराम से बैठने की कोई जगह नहीं होती। हमारी जनता में के १७ करोड़ से अधिक द्वारा नव-निर्वाचित आप संसद् के सदस्य ऐसे यात्री हैं जिन्हें उनके साथ साथ आगे बढ़ना है। आपका यह बड़ा सौभाग्य है और आपकी भारी जिम्मेदारी है।

इस ऐतिहासिक मौक़े पर जब मैं आपके सामने बोल रहा हूं मुझे अपने प्राचीन देश और उस में बसने वाले करोड़ों नर नारियों के बड़े भाग्य का कुछ आभास है। भाग्य हमें बुला रहा है और यह हमारा काम है कि हम उसके निमन्त्रण को स्वीकार करें। वह आवाहन तो महान् देश भारत को, जिसने कि इतिहास के ऊषाकाल से ही, जब कि सहस्रों वर्ष पूर्व उसकी कहानी शुरू हुई थी, सुदिन और दुर्दिन दोनों ही देखे हैं, सेवा के लिये है। इस दीर्घ काल में इस देश को महान् गौरव भी मिला और हमारा भाग्य विपत्तिमय भी रहा। अब जब कि हम भारत

[राष्ट्रपति]

की लम्बी कहानी के नये दौर को शुरू करने वाले हैं हमें पुनः यह निर्णय करना है कि किस प्रकार हम उसकी सर्वोत्तम सेवा कर सकते हैं। आपने और मैं ने अपने इस देश की सेवा का व्रत लिया है। मेरी प्रार्थना है कि हम अपने व्रत में सत्य निष्ठ सिद्ध हों और इसे पूरा करने के लिये अपना तन-मन-धन लगा दें।

सुदीर्घ काल की पराधीनता के बाद भारत ने अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त की है। सब कुछ सह कर भी उस स्वतन्त्रता को बनाये रखना है, बचाना है और बढ़ाना है, क्योंकि उसी स्वतन्त्रता के आधार पर ही तो प्रगति का कोई भी भवन खड़ा किया जा सकता है। किन्तु अकेली स्वतन्त्रता ही पर्याप्त नहीं है—उसे तो अपने साथ हमारी जनता को कुछ सुख लाभ कराना चाहिये और जिन बोझों से वे दबे हुए हैं उनको कम करना चाहिये। इसलिये यह बात हमारे लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गई है कि हम अपनी जनता की तेजी के साथ आर्थिक उन्नति करने के लिये जुट जायें और समता तथा सामाजिक और आर्थिक न्याय के जो उच्च आदर्श हमारे संविधान में अंकित हैं उनको पूरा करने के लिये हम प्रयास करने लगें।

अपने सारे इतिहास में भारत ने मानवात्मा की कुछ दूसरी प्रेरणाओं का प्रतिनिधित्व किया है। संभवतः भारतवर्ष का विशिष्ट लक्षण यही रहा है और अभी हाल में ही उस प्राचीन भावना के उत्तम प्रतीक को महात्मा गांधी के रूप में, जिन्होंने कि अपने नेतृत्व द्वारा स्वतन्त्रता तक हमें पहुंचा दिया, हमने देखा है। उनकी दृष्टि में राजनैतिक स्वतन्त्रता एक महत्वपूर्ण क़दम थी पर वह केवल मानवात्मा की महत्तर स्वतन्त्रता की तरफ़ एक क़दम मात्र ही थी। उन्होंने हमें शान्ति और अहिंसा का रास्ता दिखाया किन्तु वह शान्ति कब्र की शान्ति नहीं है और न वह अहिंसा बुजदिलों की अहिंसा है। और भारत के प्राचीन ऋषियों और महात्माओं की शिक्षा के अनुकूल ही उन्होंने हमें यह सिखाया कि घृणा और हिंसा द्वारा कोई बड़ा उद्देश्य नहीं सध सकता और उचित लक्ष्यों की साधना और प्राप्ति केवल उचित साधनों द्वारा ही हो सकती है। न केवल हम भारतवासियों के लिये ही वरन् मैं यह भी कहूंगा कि संसार भर के लोगों के लिये यह एक बुनियादी सबक़ है।

मेरा यह हार्दिक विश्वास है कि जो बड़े काम हमारे सामने हैं उनके करने में भारत के इस प्राचीन तथा चिर-नवीन संदेश को आप याद रखेंगे और सहयोगात्मक प्रयास की भावना से और सब निम्न उद्देश्यों के ऊपर राष्ट्र और मानवता के हित को मानकर कार्य में लगेंगे। हमको भारत की एकता का अर्थात् अपने भावी उच्च भाग्य की प्राप्ति के लिये क्रियाशील स्वतन्त्र लोगों की एकता का निर्माण करना है। इसलिये हमें उन सब प्रवृत्तियों की जो इस एकता को क्षीण करती हैं तथा हम लोगों में से एक दूसरे के बीच में दीवारें, साम्प्रदायिक दीवारें, प्रान्तीयता की दीवारें और जांतपात की दीवारें खड़ी करती हैं, खत्म कर देना है। अनेक राजनैतिक और आर्थिक विषयों पर मतभेद होगा और होना चाहिये किन्तु यदि भारत और उसके लोगों का हित ही हमारी प्रधान प्रेरणा हो और हम इस बात को समझें—और इसे तो हमें समझना ही चाहिये—कि इस हित की प्राप्ति पारस्परिक सहयोग और प्रजातन्त्रात्मक रीतियों से ही की जा सकती है तो ये मत-भेद हमारे सार्वजनिक जीवन को समृद्ध ही करेंगे।

मेरा आपसे निवेदन है कि इस दृष्टि-कोण से इस देश में आप अपनी समस्याओं का मुक़ाबला करें और मैत्री भावना से और निर्भय हो कर दुनिया के प्रति व्यवहार करें। आज भय, किसी आने वाली विपत्ति का भय, सारी दुनिया को अन्धकार में डाले हुये है। भय से न तो किसी व्यक्ति का और न किसी देश का उत्कर्ष होता है, वह तो जैसा हमारे प्राचीन ग्रन्थों में लिखा हुआ है केवल अभय से ही हो सकता है।

हमने संसार के सभी देशों से मैत्री की नीति बराबर बरती है। और यद्यपि कभी कभी इसके बारे में भ्रान्ति हुई है तो भी इस नीति को दूसरे लोग अधिकाधिक समझने लग गये हैं और इसका फल निकलने लगा है। मैं भरोसा रखता हूं कि हम दृढ़ता से इस नीति पर चलते रहेंगे और आज दुनिया के बहुतेरे भागों में जो तनातनी है उसको कुछ कम करने का इस प्रकार प्रयास करेंगे। हमारी सरकार ने दूसरे देशों के साथ इसी तरह ही दस्तन्दाजी नहीं करनी चाही है जिस प्रकार कि वह हमारे अपने देश में दूसरों की दस्तंदाजी पसन्द नहीं करती। जहां कहीं सम्भव हुआ है हमने सहयोग की रीति से ही काम लिया है और शान्ति स्थापना में अपनी सहायता देने के लिये हम हमेशा तैयार हैं। हम अपनी सहायता को किसी पर लादने की इच्छा नहीं रखते किन्तु हम इस बात को समझते हैं कि आज की दुनिया में कोई देश बिल्कुल अलग होकर नहीं रह सकता और यह अनिवार्य है कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ता रहे ताकि किसी सुदूर भविष्य में मानव जाति की उन्नति के लिये महान् सहयोगात्मक प्रयास में संसार के सारे राष्ट्र सम्मिलित हो जायें।

प्रायः एक वर्ष से इस बात के लिये कोरिया में प्रयत्न हो रहे हैं कि विराम-संधि का कोई रास्ता निकल आये जिससे कि उन बहुतेरी समस्याओं का जो सुदूरपूर्व एशिया को सता रही हैं शान्तिमय निपटारा हो सके। मैं ने यह आशा कई बार प्रकट की है कि ये प्रयत्न सफल होंगे और शान्ति फिर से स्थापित हो जायेगी। यह महानतम दुर्घटना है कि कोरिया की जनता के लिये सद्भावना के कथनों के बावजूद वह देश लड़ाई, भूख, और महामारियों के कारण एकबारगी ही बर्बाद हो गया है। संसार के लिये यह एक चिन्ह और चेतावनी है कि युद्ध का क्या फल होता है चाहे फिर उसके पक्ष में किसी प्रकार की तात्कालिक सफ़ाई क्यों न पेश की जाये। युद्ध से कोई समस्या हल नहीं होती बल्कि वह तो समस्यायें पैदा करता है। अब ऐसा मालूम होता है कि कोरिया में विराम-संधि में जो भी रुकावटें थीं वह क़रीब क़रीब सब दूर हो गयी हैं और एक ही बड़ी रुकावट रह गयी है—वह है युद्ध-बन्दियों की अदला बदली। इस अन्तिम रुकावट को दूर करना नीतिज्ञों की बुद्धि से परे नहीं होना चाहिये। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इस का यह अर्थ होगा कि न केवल बुद्धि की ही बल्कि सामान्य मानवता की हार हमने मान ली। आज संसार शांति का भूखा है और जो नीतिज्ञ शान्ति ला सकेंगे वे एक ऐसे भारी और भयावह बोझ को दूर करेंगे जो आज संसार भर में करोड़ों लोगों के मन को व्यथित कर रहा है।

मैं ने पहले कई बार एशिया और अफ्रीका के विभिन्न प्रदेशों के, जो अब तक स्वतन्त्रता से वंचित हैं, महान् राष्ट्रीय भावना की बड़ी लहर का जिक्र किया है। विशेषतया ट्यूनीशिया की हाल की घटनाओं का मैं ने जिक्र किया है और उस देश के लोगों की स्वतन्त्रता की अभिलाषा के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की है। मुझे इस बात का

[राष्ट्रपति]

बड़ा अफ़सोस है कि एशिया और अफ्रीका के बहुत से देशों की इच्छा के बावजूद संयुक्त राष्ट्र में इस विषय पर विचार विमर्श तक नहीं करने दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संस्था तो विश्वसमुदाय के, जिसमें कि सब जातियां सम्मिलित हैं, प्रतिनिधित्व के लिये बना था तथा उस का मुख्य उद्देश्य शांति बनाये रखना था। शनैः शनैः संयुक्त राष्ट्र के संस्थापकों के तथा उन्होंने जो अधिकारपत्र बनाया था उसके महान् उद्देश्य धुंधले पड़ते जा रहे हैं और उनकी व्यापक दृष्टि का स्थान अपेक्षाकृत सीमित दृष्टिकोण ले रहा है। विश्व भावना का विचार अपेक्षाकृत संकुचित भावना में परिणित हो रहा है और शान्ति की प्रेरणा क्षीण पड़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संस्था मानव जाति की अहम आवश्यकता की पूर्ति करने के लिये हुई थी। यदि वह इस आवश्यकता की पूर्ति करने में असफल होती है और शान्ति की रक्षा और स्वतन्त्रता की अभिवृद्धि करने का प्रभावहीन साधन मात्र रह जाती है तो वास्तव में यह एक भारी दुखद् घटना होगी। मेरी यह उत्कट आशा है कि यह महान् संस्था जिसके साथ संसार की आशायें बंधी हुई हैं अपने पुराने आदर्श पर लौट आयेगी और यह शान्ति और स्वतन्त्रता का स्तम्भ बन जायेगी जैसा बनने की कि इससे अपेक्षा थी।

हमारी सरकार ने हमारे महान् पड़ोसी चीन को एक सांस्कृतिक शिष्ट मंडल भेजा है। वह शिष्ट मंडल हमारे लोगों का चीन के लोगों के प्रति अभिनन्दन और सद्भावना ले कर गया है। चीन की सरकार और चीन के लोगों ने उसका जो हार्दिक स्वागत किया है उसके लिये मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं।

मुझे बहुत अफ़सोस है कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार की जातीय नीति अभी भी जारी है और उसके कारण गम्भीर परिस्थिति पैदा हुई है। हमारे लोग इस नीति से बहुत चिन्तित हैं क्योंकि भारतीय उद्भव के अनेक लोग दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। किन्तु यह सवाल अब दक्षिणी अफ्रीका के हिन्दुस्तानियों का ही केवलमात्र प्रश्न नहीं रह गया है। अब तो उसका महत्व कहीं अधिक बड़ा और विस्तृत हो गया है। यह जातिगत आधिपत्य और जातिगत असहिष्णुता का प्रश्न है। अफ्रीका में रहने वाले हिन्दुस्तानियों से भी कहीं अधिक अब यह अफ्रीका के रहने वालों के भविष्य का प्रश्न है। इस सवाल और ऐसे ही सवालों के निबटारे में विलम्ब करना समस्त मानव जाति के लिये संकटपूर्ण है। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि सारे अफ्रीका में अफ्रीका के रहने वालों और वहां रहने वाले हिन्दुस्तानियों के बीच में मैत्रीभाव बढ़ रहा है। हमारी इच्छा अफ्रीका के लोगों की उन्नति में लेशमात्र हस्तक्षेप करने की नहीं है बल्कि जहां तक हो सके हम उनकी सहायता करना चाहते हैं।

मुझे यह भी खेद है कि लंका में बहुत दिनों से रहने वाले अनेक भारतीय मत देने के अधिकार से वंचित कर दिये गये हैं। वे लंका के वैसे ही नागरिक होने का दावा करते हैं जैसे कि उस देश के अन्य निवासी करते हैं। लंका से हमारे सम्बन्ध सहस्रों वर्षों से हैं और लंका के और उसके लोगों से हमारे सम्बन्ध अत्यन्त मैत्रीपूर्ण रहे हैं। हमने लंका की स्वतन्त्रता का स्वागत किया था और हम यह आशा करते थे कि उसके लोग स्वतन्त्र जाति की हैसियत से हर प्रकार की प्रगति करेंगे। पर वहां के नागरिकों की एक बड़ी संख्या को उनके अपने नैसर्गिक स्वत्वों से वंचित कर देने से सच्ची

प्रगति नहीं हो सकती । उससे तो बहुतेरे जटिल प्रश्न और उलझनें ही पैदा हो सकती हैं जैसी कि हो भी गई हैं ।

पिछले अनेक वर्षों से हमारे यहां खाद्य पदार्थों की कमी रही है और बड़ी मिकदार में अन्न बाहर से लाना पड़ा है । इस काम में अमेरिका के संयुक्त राज्य से हमें बड़ी सहायता मिली है और उस महान् देश ने जो उदारतापूर्ण सहायता की है उसके लिये हम कृतज्ञ हैं । हाल के इतिहास में आज पहले पहल चावल को छोड़ कर और सब अन्नों का हमारे पास बड़ा भण्डार है और हम एक बड़ा भण्डार बना रहे हैं जो आगे जरूरत के वक्त हमें मदद देगा । इस बात का तो हमें स्वागत करना चाहिये । किन्तु देश के बड़े भागों में वर्षा नहीं होने से वहां के लोगों के लिये कठिन समस्या पैदा हो गई है । लगातार पांच सालों तक रायल-सीमा में अनावृष्टि की मुसीबत सहनी पड़ी है और वहां आज सब से बड़ी जरूरत की चीज पानी है । कुएं गहरे करके, पानी ढो कर और दूसरे प्रकार से जनता की सहायता करने का बहुत अच्छा काम हमारी सेना वहां कर रही है । इन सूखे और अन्नाभाव के प्रदेशों में अनेक छोटी मोटी योजनाएं हाथ में ली गई हैं जिनके द्वारा लोगों को काम मिल रहा है और सस्ते गल्ले की दुकानें खोली गई हैं । जहां जरूरत मालूम पड़ती है वहां मुफ्त खाना भी दिया जा रहा है ।

विदेशों से आये हुये अन्न की अधिक कीमत होने के कारण अन्न का दाम चढ़ गया है । सरकार की ओर से घाटा सहकर जो मदद अन्न सस्ता बेचकर की जाती थी उसे कम कर देने से भी कीमतों में यह अधिकाई हुई है और जहां जहां नाप तोल कर अन्न बांटा जाता था वहां लोगों की तकलीफ़ कुछ बढ़ी है और कुछ असन्तोष पैदा हुआ है । इसके असर को चीजों के दाम गिर जाने ने कुछ कम कर दिया है । अन्न सम्बन्धी सहायता कम कर दिये जाने की वजह से कई राज्यों की सरकारों ने अन्न आयात करने की अपनी आवश्यकता का वास्तविकता की दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक ठीक अनुमान लगाया है और इससे जो अन्न की मांग राज्यों से आया करती थी वह कुछ जगहों में कम हो गई है और फलतः उनका आयात कम हो जायेगा । यह आज की स्थिति में और आगे के लिये भी अवश्य ही लाभदायक है । जो राशि अन्न सम्बन्धी मदद न देने से बची है वह छोटी मोटी आवश्यक योजनाओं में लगा दी जायेगी जिनसे आगे अन्न की उत्पत्ति बढ़ेगी और इस तरह हमें अपनी खाद्य समस्या के हल करने में मदद मिलेगी । हमारी सरकार इन सब बातों पर बहुत ध्यान से विचार कर रही है । उसे तात्कालिक और भविष्य के लाभ को आपस में मुकाबला करके देखना है । साथ ही वह इस बात के लिये भी बहुत फ़िक्रमन्द है कि लोगों को कोई कष्ट न हो और उससे जो कुछ हो सकेगा वह इस विपत्ति को टालने के लिये करेगी ।

योजना आयोग अपनी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दे रहा है । इस योजना में एक महत्वपूर्ण बात और जोड़ी गयी है, वह है देश भर में ५५ सर्वोन्नति योजनाओं का प्रस्ताव । अमेरिका के संयुक्त राज्य के टैक्निकल कोआपरेशन प्लैन द्वारा दी गयी सहायता से ही यह सम्भव हो सका है । इस सर्वोन्नति योजना का प्रयोजन न केवल खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाना ही है बल्कि उससे भी कहीं अधिक यह है कि सब लोगों का रहन सहन का स्तर ऊंचा किया जाये । आशा की जाती है कि यह योजना उन्नति करेगी और भारत के एक बड़े

[राष्ट्रपति]

भूभाग में फैल जायेगी। मगर यह तभी बढ़ सकती है जब इसे जनता का पूरा सहयोग मिले और यह मेरा हार्दिक विश्वास है कि इस बात में भी जैसे कि योजना आयोग के और दूसरे प्रस्तावों को पूरा करने में उसका पूरा पूरा सहयोग मिलेगा।

कृषि द्वारा उत्पादन के मिले जुले कार्यक्रम ने संतोषप्रद उन्नति की है। बमुक़ाबले १९४७-४८ के जब पटसन की उत्पत्ति १६·६ लाख गांठ थी १९५१-५२ में वह बढ़ कर ४६·८ लाख गांठ हो गई है। इन्हीं दिनों में रूई की उत्पत्ति २४ लाख गांठ की जगह ३३ लाख गांठ हो गई है। अन्न की उत्पत्ति १४ लाख टन बढ़ गई है यद्यपि कुछ प्रदेशों में सूखा पड़ जाने से इस बढ़त का लाभ नहीं हो पाया है। १९४७-४८ में १०·५ लाख टन चीनी बनी थी जो १९५१-५२ में बढ़ कर १३·५ लाख टन हुई है। इस्पात, कोयले, सीमेंट और नमक की भी उत्पत्ति बढ़ी है। नमक के मामले में भारत अपनी जरूरतों को पूरा कर लेता है और जो बच जाता है उसे देश से बाहर भी भेजता है। सौराष्ट्र में एक केन्द्रीय नमक अनुसन्धान स्थान क़ायम किया जा रहा है।

हमारी सरकार देश की आर्थिक स्थिति पर बराबर ग़ौर करती रही है। मैं ने संसद् के अपने पिछले अभिभाषण में थोक दामों में थोड़ी कमी का ज़िक्र किया था। यह कमी की ओर झुकाव फरवरी और मार्च के महीनों में और ज़ोर से बढ़ गया। कुछ अंश में यह तो सारी दुनिया में चीज़ों की क़ीमतों के पुनर्संयोजन के कारण हुआ। जो कमी १९५० में ही शुरू हुई थी वह कोरिया में लड़ाई आरम्भ हो जाने की वजह से कुछ रुक सी गयी थी। कोरिया में विराम-संधि की आशा की झलक से क़ीमतों के पुनर्संयोजन की यह प्रक्रिया ज़ोर पकड़ गई है। देश में ज्यादा माल पैदा होने की वजह से और उपभोक्ताओं द्वारा ऊंची क़ीमतों का अधिकाधिक विरोध करने से इस पुनर्संयोजन के झुकाव को और भी मदद मिली है। रुपये और साख सम्बन्धी सरकारी नीति ने भी जो मुद्रा स्फीति रोकने के ख़याल से शुरू की गयी थी दामों को गिराने में मदद की है। जो लोग वाणिज्य और कारबार में लगे हैं और विशेष करके कपड़े और पटसन की बुनाई के कारबार वाले, दामों की इस तेज़ी से गिर जाने से कुछ दिक्क़त में पड़ गये हैं। इससे हमारे निर्यात से जो आमदनी होती है उसमें भी कमी होने लग गयी है। हमारी सरकार स्थिति को बहुत ध्यानपूर्वक देख रही है जिसमें इसका हमारे यहां के उत्पादन और लोगों को धंधा मिलने पर कोई बुरा असर न पड़े। उसका इरादा है कि दामों को एक मुनासिब स्तर पर ठहरा देने के लिये जो कार्रवाई ज़रूरी हो वह करेगी।

इस बात की मुझे बड़ी ख़ुशी है कि एक नया उत्पादन मन्त्रालय क़ायम किया गया है। सरकार के कारख़ानों के उत्पादन का बड़ा महत्व है और इस काम के लिये एक नये मन्त्रालय की स्थापना से स्पष्ट है कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

सरकार ने पिछले वर्ष संसद् को आश्वासन दिया था कि एक प्रेस कमीशन समाचार-पत्रों सम्बन्धी विविध प्रश्नों पर विचार करने के लिये मुक़र्रर किया जायेगा। हमारी सरकार को आशा है कि वह निकट भविष्य में ही ऐसा कमीशन नियुक्त करेगी। ऐसा सोचा गया है कि संसद् के सामने प्रेस लौज इन्क्वायरी कमेटी की सिफ़ारशों से उद्भूत एक विधेयक उपस्थित किया जाये।

संसद् का यह सत्र विशेष करके बजट का काम करेगा और दूसरे प्रकार के क़ानून बनाने के लिये शायद बहुत समय नहीं मिलेगा। १९५२-५३ के वित्तीय वर्ष के लिये भारत सरकार की आय व्यय का अनुमानपत्र पेश किया जायेगा और लोक सभा के सदस्यों को जो ख़र्च के लिये मांगें होंगी उनको विचार करके पारित करना होगा।

अन्तर्कालीन संसद् के अन्तिम सत्र के बाद सौराष्ट्र (एबोलिशन आफ़ लोकल सी कस्टम्स ड्यूटीज़ एण्ड इम्पोज़ीशन आफ़) पोर्ट डेवलपमेंट लेवी का निरसन करने के लिये एक अध्यादेश का परख्यापन करना आवश्यक हो गया था। वह अध्यादेश आपके सामने एक नये विधेयक के रूप में आयेगा और आपसे निवेदन किया जायेगा कि आप उस पर विचार कर और उसको पारित करें। एक दूसरा अध्यादेश डिस्प्लेस्ड परसन्स क्लेम्स ऐक्ट १९५० को जारी रखने के लिये जारी किया गया था। उस अध्यादेश की जगह पर भी आपके सामने एक विधेयक उपस्थित किया जायेगा।

कई विधेयक जो अन्तर्कालीन संसद् में पेश किये गये थे अब व्यपगत हो गये हैं। जहां तक समय मिलेगा उन में से कुछ को आपके सामने रखा जायेगा। यह भी विचार है कि संसद् के सामने निवारक अवरोध सम्बन्धी विधेयक भी रखा जाये।

एक विधि सम्बन्धी प्रस्ताव जिस पर अन्तर्कालीन संसद् में काफ़ी बहस हुई थी हिन्दू कोड बिल था। यह पारित नहीं हो सका था और दूसरे विधेयकों के साथ यह भी व्यपगत हो गया है। हमारी सरकार का यह इरादा है कि इस विषय पर एक नया विधान पेश किया जाये। किन्तु यह सोचा गया है कि इस विधेयक के कई भाग कर दिये जायें और प्रत्येक भाग को संसद् के सामने अलग-अलग उपस्थित किया जाये जिसमें उस पर विचार करना और उसे पारित करना आसान हो जाये।

मैंने यह प्रयत्न किया है कि संसद् के इस सत्र में जो काम आपके सामने आयेंगे उनमें से कुछ को आपको बता दूं। मुझे आशा है कि आपका परिश्रम हमारे देश के कल्याण के लिये सफल होगा और यह भारत के गणतन्त्र का नयी संसद् मैत्रीपूर्ण सहयोग और योग्यतापूर्वक काम करने की एक मिसाल पेश करेगी। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि कहां तक सहिष्णुता की भावना से आप अपने सारे कामों में काम लेते हैं और कहां तक आपके सारे प्रयास सद्बुद्धि से आलोकित हैं। मेरा यह हार्दिक विश्वास है कि यह बुद्धिमत्ता और सहिष्णुता की भावना आपको बराबर अनुप्राणित करेगी।

The President: Members of Parliament, I welcome you here today as Members of the first Parliament of the Republic of India, elected under our Constitution. We have now given full effect to the provisions of the Constitution, relating to the composition of the Legislatures and the Headship of the State, and thus completed one stage of our journey. Even as we complete that stage, we start on another. There is no resting place for a nation or a people on their onward march. You, Members of Parliament, newly elected by over 170 millions of our people, are the pilgrims who have to march forward in their company. On you rests a unique privilege and a heavy responsibility.

As I speak to you on this historic occasion, I have a feeling of the high destiny of our ancient land and the vast numbers of men and women who live in it. Destiny beckons to us and it is for us to respond to its call. That call is for the service of this great land of India, which has passed through good fortune and ill-fortune alike since its story began, many thousands of years ago, at the dawn of history.

[The President]

During these many years, greatness has come to our land and tragedy has also been our fate. Now that we stand on the threshold of another phase of India's long story, we have to determine afresh how best to serve her. You and I have taken the oath of service to this country of ours. May we be true to that pledge and dedicate our highest endeavour to its fulfilment.

India has, after a long period of subjection, gained her freedom and independence. That freedom has to be maintained, defended and enlarged at all cost, for it is on the basis of that freedom alone that any structure of progress can be built. But freedom by itself is not enough—it must also bring a measure of happiness to our people and a lessening of the burdens they suffer from. It has, therefore, become of vital importance for us to labour for the rapid economic advancement of our people and to endeavour to realise the noble ideals of equality and social and economic justice which have been laid down in our Constitution.

India has represented throughout her history certain other urges of the human spirit. That has, perhaps, been the distinguishing mark of India, and even in recent years we saw a noble example of that ancient spirit and urge of India in the form of Mahatma Gandhi, who led us to freedom. To him, political freedom was a vital step, but only a step to the larger freedom of the human spirit. He taught us the way of peace and non-violence, but not the peace of the grave or the non-violence of the timid. And he taught us, in line with the teachings of India's ancient sages and great men, that it is not through hatred and violence that great ends are achieved, that right ends must be pursued and achieved only through right methods. That is a basic lesson not only for us of India but, if I may venture to say so, for people throughout the world.

I earnestly trust that, in the great tasks that face us, you will remember this ancient and ever-new message of India and will work in a spirit of co-operative endeavour, placing the cause of the nation and of humanity above all lesser objectives. We have to build up the unity of India, the unity of a free people working for the realisation of the high destiny that awaits them. We have, therefore, to put an end to all tendencies that weaken that unity and raise barriers between us, the barriers of communalism, provincialism and casteism. Opinions will and must differ in regard to many political and economic matters, but if the good of India and her people is our dominant urge and we realise, as we must, that this good can only be achieved through the methods of peaceful co-operation and democratic processes, then these differences can only add to the richness of our public life.

It is with this outlook that I beg of you to face your problems here in this country and to face the world with friendly eyes and without fear. Fear today, fear of some approaching disaster, darkens the world. It is not through fear that the individual or the nation grows, but through fearlessness, *abhaya*, as our ancient books told us.

We have consistently pursued a policy of friendship with all the countries of the world and that policy, though sometimes misunderstood, has been progressively appreciated by others and is yielding fruit. I trust that we shall firmly continue that policy and thus try to lessen somewhat the tension that exists in many parts of the world. My Government has not sought to interfere with other countries just as it does not invite any interference from others in our own country. We have tried the method of co-operation wherever possible and our good offices are always available to further the cause of peace. We have no desire to thrust them on anyone. We realise, however, that in the world today no country can remain isolated, that it is inevitable that international co-operatoin should grow till, at some distant date, all the nations of the world join together in a great co-operative endeavour for the advancement of humanity.

For nearly a year now, efforts have been made in Korea to find some way to a truce which might lead to a peaceful settlement of the many problems that afflict the far-east of Asia. I have expressed the hope on several occasions that success will crown these efforts and peace be established again. It is the greatest of tragedies that, despite assertions of goodwill for the Korean people, this ancient country has been reduced by war, hunger and pestilence to utter ruin. It has become a signal and a warning to the world of what war means, whatever immediate justification might be advanced for it. War does not solve problems, it creates them. In Korea now it appears that most of the obstacles to a truce have been overcome and only one major hurdle, the exchange of prisoners, remains. It should not be beyond the wit of statesmen to overcome this last obstacle. Not to do so will be to confess the failure not only

of wisdom but of common humanity. The world hungers for peace and the statesmen who bring peace will remove a heavy and fearful burden that now oppresses the minds of hundreds of millions of people throughout the world.

I have referred on previous occasions to the great nationalist upsurge in various parts of Asia and Africa which are still denied freedom. In particular, I have made reference to recent events in Tunisia and expressed our sympathy for the people of that land in their desire for freedom. I regret greatly that, in spite of the desire of a large number of countries in Asia and Africa, even a discussion of this subject was not allowed in the United Nations. The United Nations Organisation was meant to represent the world community, inclusive of all, and its primary aim was the preservation of peace. Gradually, the noble aims of the founders of the United Nations and the Charter that they framed appear to be getting blurred. The wide vision gives place to a more limited outlook. The conception of universality changes into something far narrower and the urge to peace weakens. The United Nations Organization came into existence to fulfil a deeply felt want of humanity. If it fails to fulfil that want and becomes an ineffective organ for the maintenance of peace and the advancement of freedom, that, indeed, will be tragedy. I earnestly trust that this great organisation, on which the hopes of the world have been built up, will return to its old moorings and become, as it was meant to be, a pillar of peace and freedom.

My Government has sent a Cultural Delegation to our great neighbour, China. That Delegation has carried the greeting and goodwill of our people to the people of China. I should like to express my gratitude for the cordial welcome that it has received from the Government and people of China.

I regret greatly that the racial policy of the Government of the Union of South Africa has continued and has led to serious developments. Our people have been intimately concerned over this policy because there are many people of Indian origin who live in South Africa. But this question is no longer merely one of Indians in South Africa; it has already assumed a greater and wider significance. It is a question of racial domination and racial intolerance. It is a question of the future of Africans even more than that of Indians in South Africa. Delay in settling this and like questions is fraught with peril for humanity. I am glad that there has been a growth of friendly relations all over Africa between the Africans and the Indians resident there. It is our desire not to interfere in any way with the growth of the peoples of Africa, but to help them to the best of our ability. I regret also that a large number of Indians, long resident in Ceylon, have been deprived of their voting rights. They claim to be as much Ceylonese citizens as other inhabitants of that country. Our ties with Ceylon go back to thousands of years and our relations with Ceylon and her people have been most friendly. We welcomed her independence and we hoped that her people would advance in every way as an independent people. But true progress will not come by depriving a large number of citizens of their natural rights. This will lead, as it has already led, to serious problems and complications.

We have for many years past suffered a shortage of food and large quantities of foodgrains have had to be imported. In this we were helped greatly by the United States of America, and we must be grateful to that great country for the generous help that it gave. For the first time in recent history, we have large stocks of foodgrains (except for rice), and are building up a substantial reserve which will help us in the future in case of need. This is to be welcomed. But the failure of the rains over large parts of our country has created a difficult situation for the people there. For five successive seasons, Rayalaseema has suffered the misfortune of a drought and its greatest need today is water. Our army is doing valuable work to help the civil population by deepening wells and carrying water and in other ways. In these large areas of drought and scarcity, many minor projects have been undertaken to provide work and cheap grain shops have been opened. Wherever necessary, free food is given.

Owing to the high cost of imported foodgrains, their price has gone up. The contraction of the food subsidy has contributed in some measure to those high prices, and has caused some distress and discontent in rationed areas. To some extent this is partly counterbalanced by a general fall in prices. The limitation of food subsidies has induced Governments in various States to make a more realistic appraisal of their need for import of foodgrains, and this has led to a reduction of the demand from various States for foodgrains, with its consequent result on their import. This is undoubtedly an advantage in the present and for the future. The amount saved from the

[The President]

food subsidies has been diverted to financing minor irrigation schemes which will yield more foodgrains in future and thus help in solving our food problem. My Government is giving the most careful attention to these matters. It has to balance immediate with future advantages. At the same time it is anxious that no distress should be caused and it will do all in its power to prevent this from happening.

The Planning Commission is now finalising its report on the Five-Year Plan. A very vital addition to this Plan has been made by the proposal to start fifty-five Community Projects throughout the country. This has been possible because of aid from the United States of America through their Technical Co-operation Plan. These Community Projects are not only intended to increase our food production but, what is even more important, to raise the whole level of community living. It is hoped that this programme will grow and cover a considerable part of India. But it can only grow if it has the full co-operation of the people and I earnestly trust that in this matter, as in implementing the other proposals of the Planning Commission, their co-operation will be forthcoming in full measure.

The integrated programme for agricultural production has made satisfactory progress. Jute production has increased considerably from 16·6 lakhs of bales in 1947-48 to 46·8 lakhs of bales in 1951-52. Cotton production has gone up during the same period from 24 lakhs bales to over 33 lakhs bales. Production of foodgrains has increased by 14 lakhs tons, though this has been offset by drought in certain areas. Sugar production increased from 10·75 lakhs tons in 1947-48 to 13·5 lakhs tons in 1951-52. There has also been an increase in the production of steel, coal, cement and salt. India is now self-sufficient in salt and is able to export her surplus. A Central Salt Research Station is being established in Saurashtra.

The general economic situation in the country has been kept under continuous observation by my Government. In my last address to Parliament I referred to a slight fall in whole-sale prices. This trend was sharply accentuated in the months of February and March. Partly this was due to a general re-adjustment of prices all over the world, a process which started in 1950 but received a setback owing to the outbreak of the Korean war. With the prospect of an armistice in Korea in sight, this process of readjustment gathered strength. This has been assisted by an increased production of goods in the country coupled with increasing consumer resistance to high prices. The monetary and credit policy of my Government, initiated with a view to checking inflation, has also contributed to the fall in prices. This sharp fall in the price level has caused difficulties to those engaged in business and industry, more especially in the textile industry. This is also leading to a fall in our export earnings. My Government are closely watching the situation to ensure that production and employment are not affected. It is their intention to take such action as might be necessary to assist in the stabilisation of prices at a reasonable level.

I am glad that a new Ministry of Production has been created. Production by State-owned industries is of vital importance and the creation of a new Ministry for this purpose indicates that special attention is going to be paid to it.

An assurance was given by Government last year to Parliament that a Press Commission would be appointed to consider various matters connected with the Press. My Government hope to appoint such a Commission in the near future. It is also proposed to place before Parliament a Bill arising out of the recommendations of the Press Laws Enquiry Committee.

This session of Parliament will be mainly concerned with the Budget and there will probably not be much time for other legislation. A statement of the estimated receipts and expenditure of the Government of India for the financial year 1952-53 will be laid before you. The members of the House of the People will be required to consider and pass the Demands for Grants.

After the last session of the provisional Parliament, it became necessary to promulgate an Ordinance relating to the repealing of the Saurashtra (Abolition of Local Sea Customs Duties and imposition of) Port Development Levy. This Ordinance will be brought before you in the form of a new Bill and you will be asked to consider and pass it. Another Ordinance was issued for the purpose of extending the Displaced Persons (Claims) Act, 1950. A Bill to replace this Ordinance will also be placed before you.

A number of Bills which were introduced in the provisional Parliament have now lapsed. Some of these will be placed before you in so far as time

permits. It is also proposed to place before Parliament a Bill dealing with Preventive Detention.

One of the legislative measures which was discussed at considerable length in the provisional Parliament was the Hindu Code Bill. This could not be passed and, in common with other pending Bills, has lapsed. It is the intention of my Government to introduce afresh legislation on this subject. It is proposed, however, to divide up the Bill into certain parts and to place each part separately before Parliament, so as to facilitate its discussion and passage.

I have endeavoured to indicate to you some of the work that will be placed before this session of Parliament. I trust that your labours will bear fruit for the good of our people and that this new Parliament of the Democratic Republic of India will set an example of friendly co-operation and efficient working. Your success will depend on the spirit of tolerance that governs your activities and the wisdom that inspires your efforts. I earnestly trust therefore that this wisdom and tolerance of spirit will always be with you.

PRESIDENT'S ASSENT TO BILLS

Secretary: I beg to lay on the Table a statement showing the Bills which were passed by the Provisional Parliament during the Fifth Session, 1952, and assented to by the President. [*See* Appendix I, annexure No. 1].

MOTIONS FOR ADJOURNMENT

FOOD SUBSIDIES

Mr. Speaker: I have received three notices of three differently worded adjournment motions, two from Shri K. Subrahmanyam and one from Shri A. K. Gopalan. They all deal practically with the question of food subsidies, and they wish to discuss the matter. The position is that so far as the importance of the matter is concerned, so far as the definiteness of the motions are concerned and so far as the urgency of the matter is concerned, I am in full agreement with the hon. Members, but the right to move adjournment motions has certain limitations. One of the limitations is that, it should not anticipate a debate in the House. The point is that, if hon. Members have a fairly good chance of raising the question on a debate, then it will not be permitted as an adjournment motion and it is also advantageous from another point of view, that, while a discussion on an adjournment motion will be restricted only to two hours and it may be talked out; in an opportunity for a debate; it can be discussed more fully provided, of course, Members want that discussion. Hon. Members know that there will be a motion of thanks coming from the Government side in respect of the President's Address and the earliest opportunity which hon. Members of this House will take will be to give notices of amendments thereto, stating that they want to discuss this question, that the address is unsatisfactory or omits to deal with the food subsidy question; and then, we have reserved three days' discussion on the President's Address, commencing from Monday the 19th, and it will be in the hands of Members themselves to discuss that subject on the President's Address. Of course, the Address is full of many subjects worth discussing. But as the President said this morning, this session will mainly be devoted to the Budget work; and the Budget discussions will now and then give a number of opportunities of raising and discussing this question, for example, in respect of the Budget of the Food Ministry; there will be chances in respect of the general discussion, chances again when a particular demand is made and a further chance again if a cut motion is sought to be moved and I think there will also be the Finance Bill.....

The Minister of Finance (Shri C. D. Deshmukh): I cannot say at the moment.

Mr. Speaker: The hon. Finance Minister is not in a position to state at present. Let us assume that perhaps there will be no chance on that occasion. Thus for the whole month, almost every day, I should say, there will be a chance of raising this question. Hon. Members will note one thing further, which, I think, goes to the root of the question differently. I have said that more than once in this House; but as a large number of Members are new, I may as well reiterate that principle. The adjournment motion is a device to bring something before the House, which is not included in the agenda or the order paper. It is something like taking up a new matter which was not intended to be taken up and of which all hon. Members had no notice whatever, when the order paper was circulated. The ordinary principle is, so far as possible, unless there is extreme urgency or emergency, nothing new should be introduced in the daily order of business in the House. It does injustice to a large number of Members who perhaps do not remain present in the

[Mr. Speaker]

House on the assumption that a certain business is coming in which they do not like to participate or do not like to discuss or oppose that particular point and if a new matter is taken up they find that something was done in their absence. So, in the interests of all, it has been the practice to allow adjournment motions as a matter of exception, where the matter is really urgent, and there is no other opportunity or chance for the House to consider that matter. These are general principles. Therefore, I do not think I should give my consent to these adjournment motions being taken up or moved in the House. There are three motions; but essentially they raise one and the same subject. I do not think I need deal with each motion separately. I should suggest that the Members who wish to move these motions are at perfect liberty to give notices of amendments to the motion of thanks that will be moved on behalf of the Government over the President's Address.

Shri Jaipal Singh (Ranchi West—Reserved—Sch. Tribes): There is one point of clarification, Sir, in regard to the explanation you have given. You have stated that you are generally in agreement with.....

Mr. Speaker: Order, order. Is the hon. Member going to discuss now.

Shri Jaipal Singh: I want a clarification of something that you have just now said. We agree, Sir, with the three qualifications that every adjournment motion must have. Then, you mentioned something about an adjournment motion anticipating a debate. I would like to know how you exactly interpret this question of urgency: what should be the gap between the anticipated debate and an adjournment motion? Is there any rule to say there must be one week or two weeks? Supposing for instance.....

Mr. Speaker: Order, order. I understand his point. Let us not discuss this point any further. It is all a matter depending on the merits and the facts of each individual case. There cannot be a rule of the thumb that one week should be there. It may be that not even a day should be permitted; in some cases, a month may elapse. It all depends on the particular case.

The hon. Member may refer to rule 62 (vi) which says:

> "the motion shall not anticipate a matter which has been previously appointed for consideration. In determining whether a discussion is out of order on the ground of anticipation, regard shall be had by the Speaker to the probability of the matter anticipated being brought before the House within a reasonable time;"

Hon. Members will certainly agree with me and I think the House will agree with me that—the House is not sitting tomorrow and is sitting on Monday; today there is no further business—just two days' time for the discussion of this important question is not an unusual delay. However, I need not explain this matter any further.

Shri H. N. Mukerjee (Calcutta North-East): May I submit, Sir, that there is a point which has perhaps escaped your attention? Mr. Gopalan's adjournment motion deals not only with food subsidy, but also the onset and continuance of terrible famine conditions.....

Mr. Speaker: Order, order. The hon. Member will see that all these points can be discussed on the Address of the President where the whole situation is before the House.

Shri H. N. Mukerjee: They can be discussed only on general lines during a debate on the Address.

Mr. Speaker: He may make any points he likes. Not only on general lines he is at perfect liberty to make specific points also.

Shri A. K. Gopalan (Cannanore): I do not want to discuss about the urgency of this motion or anything else because, Sir, you yourself have admitted about the urgency of the situation. My purpose in bringing forward this adjournment motion before any business began today is not because there was no debate on the question of food There have been so many debates during the last five years. There have been debates on Budgets; there have been adjournment motions and other things. But, the situation in the country today is that not a single man is.....

Mr. Speaker: Order, order. The hon. Member will resume his seat.

We do not want to enter into an argument as to how this House has been functioning. That is not the

point. The hon. Member may have his grievance. I quite appreciate it and I can understand it. But, I do not propose to allow any discussion on matters which are not directly connected so far as the merits and the procedure of admission are concerned. Otherwise, we shall never end.

Shri Velayudhan (Quilon *cum* Mavelikkara—Reserved—Sch. Castes) May I.....

Mr. Speaker: Mr. Velayudhan need not take the trouble now. I shall proceed further.

Shri Ramachandra Reddi (Nellore): May I say for your information, Sir, that most of the Members here have not received copies of the Rules of Procedure and Conduct of Business of this House. In the absence of that, we are not able to appreciate the proceedings that are going on.

Mr. Speaker: They will be supplied; they are under print.

Shri S. S. More (Sholapur): The difficulty is this. Unwittingly we may violate certain rules and disciplinary action may come down on us. We may be victimised on account of our ignorance of the rules.

Mr. Speaker: If there is any ignorance on their part, I shall be there to help them. I shall not dismiss any particular thing because of ignorance. If it is not in conformity with the rules, then I shall have to dismiss such a motion. That is a different matter altogether. But, I am not going to penalise any Member because he is ignorant.

Now, copies of the old rules are available. There have been a few changes in certain respects only and they are in print. If hon. Members want up-to-date rules the best course will be to refer to the Gazette in which they are published. A copy of the Gazette is available in the library. But, for the facility of Members, it was considered necessary that the entire set of rules should be printed in a separate booklet so that each hon. Member may possess his own copy. For that purpose, it has gone to the Press. It is not only a book of rules which is in print; there is besides a voluminous matter in the Press. I cannot excuse the Press for the delay. But, we can appreciate that all things cannot be done simultaneously and there is some time lag. In the meanwhile, they may adjust themselves to the procedure.

Shri S. S. More: Is that within the jurisdiction of the Department of Parliamentary Affairs?

Mr. Speaker: Printing?

Shri S. S. More: Yes.

Mr. Speaker: The Government Press is doing that. There is no Press for the Parliament, though there is a proposal for one which has been accepted. But, in the present days of scarcity of building materials, machinery and everything, even of money, it becomes difficult to set up our own Press.

PAPERS LAID ON THE TABLE

(i) SAURASHTRA (ABOLITION OF LOCAL SEA CUSTOMS DUTIES AND IMPOSITION OF) PORT DEVELOPMENT LEVY REPEALING ORDINANCE, 1952 AND (ii) DISPLACED PERSONS (CLAIMS) CONTINUANCE ORDINANCE, 1952

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha): I beg to lay on the Table, under the provisions of article 123(2)(a) of the Constitution, a copy of each of the following Ordinances promulgated by the President after the termination of the Fifth Session of the Provisional Parliament and before the commencement of the First Session of Parliament, 1952:

(i) The Saurashtra (Abolition of Local Sea Customs Duties and Imposition of) Port Development Levy Repealing Ordinance, 1952 (No. IV of 1952) [*Placed in Library. See* No. P-2/52]; and

(ii) The Displaced Persons (Claims) Continuance Ordinance, 1952 (No. V of 1952) [*Placed in Library. See* No. P-3/52.]

PANEL OF CHAIRMEN

Mr. Speaker: I have to inform hon. Members that under sub-rule (1) of Rule 8 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I nominate Shri M. Ananthasayanam Ayyangar, Pandit Thakur Das Bhargava and Shrimati Ammu Swaminadhan on the Panel of Chairmen.

ESSENTIAL GOODS (DECLARATION AND REGULATION OF TAX ON SALE OR PURCHASE) BILL

The Minister of Finance (Shri C. D. Deshmukh): I beg to move for leave to introduce a Bill to declare, in pursuance of clause (3) of article 286 of

[Shri C. D. Deshmukh]

the Constitution, certain goods to be essential for the life of the community.

Mr. Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to declare, in pursuance of clause (3) of article 286 of the Constitution, certain goods to be essential for the life of the community."

The motion was adopted.

Shri C. D. Deshmukh: I introduce the Bill.

SAURASHTRA (ABOLITION OF LOCAL SEA CUSTOMS DUTIES AND IMPOSITION OF) PORT DEVELOPMENT LEVY REPEALING BILL.

The Minister of Home Affairs and States (Dr. Katju): I beg to move for leave to introduce a Bill to repeal the Saurashtra (Abolition of Local Sea Customs Duties and Imposition of) Port Development Levy Ordinance, 1949.

Mr. Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to repeal the Saurashtra (Abolition of Local Sea Customs Duties and Imposition of) Port Development Levy Ordinance, 1949.

The motion was adopted.

Dr. Katju: I introduce the Bill.

CODE OF CIVIL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL

The Minister of Law and Minority Affairs (Shri Biswas): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Code of Civil Procedure, 1908.

Mr. Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Code of Civil Procedure, 1908."

The motion was adopted.

Shri Biswas: I introduce the Bill.

MAINTENANCE ORDERS ENFORCEMENT (AMENDMENT) BILL

The Minister of Law and Minority Affairs (Shri Biswas): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Maintenance Orders Enforcement Act, 1921.

Mr. Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Maintenance Orders Enforcement Act, 1921."

The motion was adopted.

Shri Biswas: I introduce the Bill.

NOTARIES BILL.

The Minister of Law and Minority Affairs (Shri Biswas): I beg to move for leave to introduce a Bill to regulate the profession of notaries.

Mr. Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to regulate the profession of notaries."

The motion was adopted.

Shri Biswas: I introduce the Bill.

The House then adjourned till a Quarter to Eleven of the Clock on Monday, the 19th May, 1952.